

## भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत मध्य प्रदेश शासन की अधिसूचना

अधिसूचना क्रमांक 7536-दस-65-दिनांक 26-6-1965 भारतीय वन अधिनियम, 1927 (संख्या 16 सन् 1927) की धारा 76 के खण्ड (घ) सहपठित धारा 60-क की उपधारा (3) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य शासन निम्न नियम बनाता है। अर्थात्-

1. इन नियमों में 'अधिनियम' का अभिप्राय है भारतीय वन अधिनियम 1927 (संख्या 16 सन् 1927)।
2. अधिनियम की धारा 80-क के अधीन बन अधिकारी के आदेश से असंतुष्ट कोई व्यक्ति आदेश की सूचना के दिनांक से 60 दिन की अवधि में अपील कर सकता है।

### 3. (1) प्रत्येक अपील-

- (क) लिखित में होगी।
- (ख) अपीलार्थी का नाम और पता विनिर्दिष्ट करेगी।
- (ग) उस आदेश का जिसके विरुद्ध वह की जा रही है दिनांक विनिर्दिष्ट करेगी।
- (घ) वह दिनांक विनिर्दिष्ट करेगी जिस दिन अपीलार्थी को आदेश की सूचना दी गई।
- (ङ) तथ्यों का स्पष्ट विवरण शामिल करेगी।
- (च) लगातार कम में उन आधारों को विनिर्दिष्ट करेगा जिन पर कि अपील प्रस्तुत की गई है किन्तु उसमें तर्कों या वृत्तान्तों का उल्लेख नहीं होगा।
- (छ) चाहे गये अनुतोष का सूक्ष्मतः उल्लेख किया जायेगा, और
- (ज) अपीलार्थी या उसके द्वारा लिखित में इस हेतु सम्यक रूप से अधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर और निम्न प्रारूप में सत्यापित होगा अर्थात्-

"मैं... .. . . . उक्त अपील के ज्ञापन में नाम दिया गया अपीलार्थी यह घोषित करता हूँ कि इसमें जो कहा गया है वह मेरे ज्ञान और विश्वास से सही है।

हस्ताक्षर

(2) अपील के ज्ञापन के साथ उस आदेश की एक प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की जायेगी इसके विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। नब तक कि अपील प्रस्तुत करते समय अपीलीय प्राधिकरण भी यह समाधान न कर दे कि चूक के लिये उचित कारण है और उस दशा में उक्त प्राधिकरण द्वारा निर्धारित अवधि में ऐसी पतिलिपि प्रस्तुत की जायेगी।

(3) अपील का ज्ञापन स्वयं अपीलार्थी द्वारा अथवा अपीलार्थी द्वारा सम्यक रूप से अधिकृत अभिकर्ता द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जायेगा या ऐसे प्राधिकरण को रजिस्टर्ड डाक से भेजा जावेगा।